हाल में दवाइयों के मामले में कोई असामान्य वृद्धि दिखाई नहीं देती है। जनवरी, 96 से दिसम्बर, 96 की अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (1981-82=100) औषधों और दवाइयों में 0.08% की वृद्धि दर्शाता है जबकि अन्य वस्तुओं के मामले में यह वृद्धि 7.3% से ज्यादा थी।

(ख) से (घ) मूल्य नियंत्रित दवाइयों के मामले में, इस बात का लिहाज किए बगैर कि इसका विनिर्माण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा अन्य के द्वारा किया जाता है के मूल्य औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1975 जो 6-1-95 को प्रख्यापित किया गया था के उपबन्धों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य नियंत्रण से बाहर आने वाली दवाईयों के मामले में जब कभी असामान्य वृद्धि जानकारी में आती है, तो मामले को संबंधित निर्माता के साथ इसका औचित्य स्पष्ट करने के लिए उठाया जाता है। अभी हाल में सूत्रयोगों के मूल्य नियंत्रण पर औषध विनिर्माताओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Subsidy to fertilizer companies

757. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the amount of subsidy given to the fertilizer companies during the last two years for selling fertilizer at a reduced rate;

(b) whether there has been any resistance on the part of the companies to accept the subsidy;

(c) if so, whether Government propose to give the subsidy directly to the farmers; and

(d) whether Government also propose to increase the subsidy considering the increase in the prices of fertilizers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) The subsidy on indigenously manufactured controlled fertilizers is paid directly to the manufacturing units. At present, only urea is covered under the Retention Price-cum-Subsidy Scheme. The subsidy payments made during 1994-95 and 1995-96 to the fertilizer companies were Rs. 4075 and Rs. 4300 crore respectively. A special concession is also available on the sale of Muriate of Potash and Di-Ammonium Phosphate(DAP), and indigenous complex fertilizers and Single Super Phosphate(SSP) under the Special Concession Scheme for decontrolled fertilizers. The Special Concession is paid to the manufacturers/importers of decontrolled fertilizers on the certification of sales made by the States. The disbursements under this scheme amounted to Rs. 514.02 crore during 1994-95 and Rs. 500 crore during 1995-96.

(b) and (c) No Sir.

(d) With effect from 21.2.97, the controlled price of urea has been raised from Rs. 3320 to Rs. 3660 per tonne. It has also been decided to increase with effect from 1.4.97 the concession on indigenous DAP from Rs. 3000 to Rs. 3750 per tonne, and on imported DAP from Rs. 1500 to Rs. 2250 per tonne, on MOP from Rs. 1500 to Rs. 2000 per tonne, on SSP from Rs. 500 to Rs. 600 per tonne and proportionately for indigenous complex fertilizers. Both these steps have been taken to reduce the imbalance in the application of NPK nutrients.

Restriction to visit Nandadevi National Park

758. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Nanda Devi National Park has been lying practically closed to the visitors and trekkers;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to open it for social, cultural and economic benefits of local people;

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. It is necessary to strictly control the entry of visitors and domestic animals into the Nanda Devi National Park for ensuring regeneration of its degraded and

polluted ecosystem. Accordingly, all trekking and mountaineering expeditions into the park have been prohibited.

(c) According to the Chief Wildlife Warden, Govt. of Uttar Pradesh, normal development activities and ecodevelopment projects are being undertaken outside the Nanda Devi National Park for the social, cultural and economic benefits of the local people.

Building up of a Captive Power Plant by Rayon Company at veraval

759. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Rayon Company propose to build up a captive power plant of 25 MW at Veraval in Gujarat;

(b) whether it is also a fact that the environmental clearance is a hindrance for the granting of permission for setting-up this captive power project;

(c) if so, the details thereof and;

(d) the time by which necessary permission is likely to be granted to the Company for setting-up the same within their premises?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (d) The Ministry had received a proposal in October, 1995 for enviornmental clearance for a 16.5 MW Captive Power Plant at Veraval, Gujarat, of M/s Indian Rayon & Industries Ltd. Since the promoters had obtained necessary State clearances prior to 27th January, 1994, the date of issue of the Environmental Impact Assessment Notification, the Environmental Clearance under the provisions of this Notification was not required for the project and project proponents informed accordingly.

वन-हनन को रोकने के लिए उठाए गए कदम

760. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनधिकृत और अंधाधुंध तरीके से बड़े पैमाने पर वन-हनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को राजस्थान सहित किसी भी राज्य से बड़े पैमाने पर वन-नाशन की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, वन-नाशन को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि को उपयोग में न लाने के लिए अधिनियमित किया गया।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 को वन और वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया।

दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों और जैविक महत्व के प्राकृतिक वासस्थलों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना, हाथी परियोजना सहित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और बाघ परियोजना रिजर्वों के बफ्फर क्षेत्रों सहित अवकृमित वन के पुनरुद्धा के लिए वनीकरण/पुनः वनीकरण और पारि-विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

लकड़ी के विकल्प, खपत को कम करने और क्षति को रोकने के लिए लकड़ी के विकल्प और ईंधन लकड़ी के बचत के उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वन और वन्यजीवों के प्राकृतिक वास-स्थलों पर दबाव कम करने के लिए वनेतर क्षेत्रों में वनीकरण और बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

लाभ बांटने के माध्यम से वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार में ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक